

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 18-II/ 16

जिला दमोह


| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 29-3-2016 | <p>मैंने आवेदक अधिवक्ता के ग्राहयता पर तर्क सुने और नस्ती में उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों एवं अन्य सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियों का, जो कि आवेदक द्वारा ही उपलब्ध कराई गई हैं, परिशीलन किया ।</p> <p>अनुविभागीय अधिकारी दमोह ने खनिज अधिकारी/निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरुद्ध अर्थदण्ड का आदेश दिनांक 29-6-12 पारित किया है, जिसके विरुद्ध अपर कलेक्टर ने प्रथम अपील दिनांक 21-5-13 को खारिज की और अपर आयुक्त ने द्वितीय अपील दिनांक 16-9-15 के आदेश से खारिज की, जिसके विरुद्ध यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत हुआ है ।</p> <p>आवेदक का प्रथम तर्क यह है कि अनुविभागीय अधिकारी ने उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश किया । इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में स्पष्ट लिखा है कि आवेदक को नोटिस तामीली हेतु भेजा गया किन्तु वे उपलब्ध नहीं हुये; घर के किसी भी सदस्य द्वारा उनके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई; एवं नोटिस लेने से इन्कार करने पर विधिवत कारण बताओ नोटिस कोटवार की उपस्थिति में मकान पर चस्पा कर तामीली कराई गई। किन्तु इसके बाद भी निर्धारित तिथि में उपस्थित ना होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई । अपर आयुक्त ने भी इस बिन्दु पर बोलता हुआ स्पष्ट निर्णय आक्षेपित आदेश में लिया है । अतः यह बिन्दु स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।</p> <p>आवेदक का शेष तर्क यह है कि नीलम खदान के मालिक को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और मौके से कोई ट्रेक्टर या जेसीबी भी जप्त नहीं हुए ।</p> <p>इस संबंधमें एक तो यह स्पष्ट है कि ट्रेक्टर एवं जेसीबी movable (चल प्रकृति के) वाहन हैं, उन्हें मौके से हटाया जा सकता है, अतः उनके जप्त ना होने से अवैध उत्खनन के तथ्यात्मक बिन्दुओं पर प्रभाव पडना नहीं माना जा सकता ।</p> <p>दूसरे, खनिज अधिकारी/निरीक्षक के प्रतिवेदन में रोड निर्माण</p> | |

(मानपुर से धनगौर खेजरा मार्ग) हेतु 600 घ0मी0 बजरे का रिवर बेड से उत्खनन पाए जाने का स्पष्ट लेख है, इससे यह स्पष्ट है कि रेत का अवैध उत्खनन हुआ था जो कि रिवर बेड से हुआ था, और इन कारणों से किसी नीलम खदान के मालिक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता, तथा यह प्रकरण ~~बह~~ म0 प्र0भू-राजस्व संहिता की धारा 247 (7) में भी आता है ।

उपरोक्त के प्रकाश में निगरानी के कोई स्वीकृति योग्य ठोस आधार नहीं होने से, यह प्रकरण अग्राह्य कर राजस्व मण्डल से समाप्त किया जाता है ।

आदेश पारित । पक्षकार सूचित हो ।

दा0द0 हो ।


29.3.16

(आशीष श्रीवास्तव)

सदस्य

M